

नव निर्माण के लिए

ISSN 2319-9407
www.yuvasamvad.org
www.yuvasamvad.com

युवा-संवाद

अप्रैल 2022

अंक-230

मूल्य - 30 रुपये

तीव्र
औद्योगिक
विकास
का भ्रम



मुसलमानों की चुनौतियां और आगे का रास्ता

युवा संवाद

वर्ष: 19 ■ अंक: 1 ■ अप्रैल, 2022
प्रकाशन एवं संपादन पूर्णतया अवैतनिक

संपादक मंडल

प्रो. कमल नयन काबरा
अरुण कुमार त्रिपाठी
अनिल चमड़िया
योगेन्द्र
अशोक भारत

संपादक

ए. के. अरुण

कला संपादक

संजीव शास्वती

संपादकीय एवं प्रबंध कार्यालय

167ए / जी.एच.2

पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

फोन - 7303608800

ईमेल : ysamvad@gmail.com

यह प्रति : 30 रु.

सदस्यता की दरें

वार्षिक : 300 रु. (व्यक्तिगत)

: 360 रु. (संस्थागत)

पांच वर्ष : 1200 रु.

दस वर्ष : 2000 रु.

आजीवन : 3000 रु.

विदेशों में : 200 यूएस डॉलर
(पांच साल के लिए)

पत्रिका के लिये सहयोग राशि 'युवा संवाद' के नाम बैंक ड्राफ्ट/चैक से युवा संवाद 167ए/जी.एच.-2, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 को भेजें। दिल्ली से बाहर के चैक के साथ 50 रु. और जोड़ें। सदस्यता राशि सीधे युवा संवाद के अकाउंट संख्या 028805003109 आई.सी.आई.सी.आई., नई दिल्ली के खाते में भी सीधे जमा कराई जा सकती है। बैंक का IFSC CODE ICIC0000288 है। राशि जमा कराने के बाद अपना नाम व पूरा पता डाक पिनकोड सहित मोबाइल नं. 09868809602 पर अवश्य एस.एम.एस. करें।

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी डॉ. ए. के. अरुण, द्वारा मर्करी प्रिंटर्स, 602, गली जूते वाली, चूड़ीवालान, दिल्ली-06 से मुद्रित एवं उन्हीं के द्वारा 167ए/जी.एच. 2, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 से प्रकाशित।

संपादक - ए. के. अरुण

RNI NO. : DELHIN/2003 / 9929

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इससे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। युवा संवाद से सम्बन्धित किसी भी विवाद का निपटारा दिल्ली की सक्षम अदालत में ही सम्भव होगा।

इस अंक में

बिहार	: बिहार में हो रही मौतों के मायने	डॉ. योगेन्द्र	7
आर्थिक बदहाली	: तीव्र औद्योगिक विकास की...	मुकेश असीम	8
वैज्ञानिक शिक्षा	: सामाजिक सरोकारों से कटती...	मनीष शर्मा	12
हिंदी पट्टी	: जड़ता की जड़ें	रामशरण जोशी	17
यूक्रेन	: भारत की दुविधा?	आकार पटेल	22
युद्ध	: विश्वयुद्ध की धमक	राधेश्याम मंगोलपुरी	24
अनावश्यक विवाद	: हिजाब पर हल्ला	राम पुनियानी	27
अल्पसंख्यक	: मुसलमानों की चुनौतियां और...	यूसुफ किरमानी	29
सुल्ली बुल्ली एप्स	: सांप्रदायिकता का ऑनलाइन...	एम असीम	36
गर्म जलवायु	: एक विकट चुनौती	प्रो. सी. के. वाष्पण्य	39
'द कश्मीर फाइल्स'	: किसकी-किसकी फाइलें खोलेंगे...	कुमार प्रशांत	44
नगालैंड	: विवादित 'अफस्पा' पर फिर बहस	दिनकर कुमार	47
बेबाक	: फिल्म देखो और देशभक्त बनो	सहीराम	49

स्थाई स्तंभ

पाठक संवाद:	4-5
संपादकीय :	6

वेब : www.yuvasamvad.org www.yuvasamvad.com



कुपोषण से भुखमरी की ओर बढ़ता 'न्यू इंडिया'!

अभी बिहार, उत्तरप्रदेश या फिर हिंदी पट्टी में मजदूरों का मिलना कठिन हो गया है। उसके पीछे जो कारण सामने आया वह था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों में मुफ्त का अनाज बांटना। सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, वृद्धा पेंशन जैसी योजना होनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य जरूर होना चाहिए किन्तु सबको मुफ्त में अन्न नहीं, बिजली नहीं। लोगों को मुफ्त में अन्न, बिजली या कपड़ा मिल जाए तो वे काम क्यों करें। वह कहते हैं यदि पेट न होता तो कोई किसी की नहीं सुनता। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिल रहे मुफ्त के राशन-पानी की जमकर आलोचना की थी। यहां तक कि प्रेस कांफ्रेंस भी किया था। उनका कहना था कि सामाजिक मद में यह सरकार जो खुलकर खजाना लुटा रही है वह अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है, किन्तु नरेंद्र मोदी उसे खुद भूल गए क्योंकि मुफ्त में वितरण कर लोगों को कर्महीन बना कर ही तो समाज में अलगाव पैदा किया जा सकता है। बेरोजगारों को भगवान अधिक याद आते हैं, कमाऊ पूत तो भगवान को याद कर उनके ऊपर एहसान कर दिया करते हैं। मोदी ने सामाजिक मद में खर्च होने वाले धन को भीख की तरह बर्बाद होने वाला बताया था और अब लोगों को उन्होंने भिखारी बनने की राह दिखा दी।

ज्ञात इतिहास में भारत सबसे अधिक विकास मनरेगा के आने के बाद से कर रहा था क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन की आमदनी हो रही थी। ली क्वान यु ने बिजली या पानी बिल माफ करने के बदले लोगों की बचत को उनकी कमाई का 45 फीसदी तक कर दिया जिसका फल यह निकला कि सिंगापुर में लोग कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। वहीं मलेशिया अपनी मलय संस्कृति को लेकर अंधेरे और गरीबी की गर्त में डूबता गया। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में मुफ्त में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की वकालत मार्क्स करते हैं। वह कहते हैं, "सभी बच्चों की सार्वजनिक विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा। अपने वर्तमान रूप में कारखानों में बच्चों के काम का अंत।" वह श्रम दायित्व की बात करते हैं न कि मुफ्त अन्न की। जब श्रम दायित्व की बात आती है तो वह कहते हैं, "प्रत्येक के लिए सामान श्रम-दायित्व, औद्योगिक सेनाओं की स्थापना, विशेषकर कृषि के लिए। कृषि का उद्योग के साथ संयोजन"। वह

कहीं भी लोगों को कर्महीन बनाने की बात नहीं करते हैं।

रघुराम राजन और लुई जिंगल्स अपनी पुस्तक सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट्स में लिखते हैं कि यदि गरीब को मुफ्त में जमीन सिर्फ इस बात के लिए सरकार द्वारा दे दी जाय जिससे कि उसकी वित्तीय सहायता होगी तो यह गलत है। वह कहते हैं, "अब जबकि इस विचार में पर्याप्त योग्यता है, यह कोई रामबाण इलाज नहीं है। यदि गरीब किसी और की निजी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं या, जैसा कि आमतौर पर विकासशील देशों में होता है, सरकारी भूमि या फिर अतिक्रमण को वैध करने से शेष भूमि पर सभी कब्जा करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र मान बैठेंगे, जिससे संपत्ति की व्यापक असुरक्षा हो सकती है, इसके विपरीत प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

कभी सोचा है कि यह मुफ्त में जो लोक कल्याणकारी राज्य के नाम पर भीख देकर अधिनायकवाद को जन्म दिया जाता है उसका खर्च कौन वहन करता है। सबसे ज्यादा उस मुफ्त को खाने वाले। मन में प्रश्न आया होगा— कैसे? समझते हैं। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने 2014-15 में सत्ता संभाली थी तो उसका बजट 30940 करोड़ रुपये का था। इस साल 2022 का बजट दिल्ली सरकार ने 69000 करोड़ रुपये कर दिया जो सात साल में दुगुना से अधिक हो गया। समर्थकों के लिए खुशी से लहालोट होने वाली बात है, लेकिन कभी सोचा कि यह 69000 करोड़ रुपये आएंगे कहाँ से। उत्तर है— कर से। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने अपने करों में बेतरतीब इजाफा किया है खैरात बाँटने के लिए। 2014-15 में बजट 30940 करोड़ रुपये का था और 2021-22 में दिल्ली सरकार कर से 43000 करोड़ रुपये उगाही की बात कर रही है— यानी 13000 करोड़ ज्यादा। यह कर कौन देगा? वही गरीब जनता क्योंकि यह कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है।

दिल्ली सरकार कहती है, "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 69000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के लिए 43000 करोड़ रुपये कर राजस्व से, 1000 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व से, 325 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से, 9285 करोड़ रुपये लघु बचत ऋण से, 1000 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियों से, 6000 करोड़ रुपये जीएसटी प्रतिपूर्ति से, 2088 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजना से। केवल 657 करोड़ रुपये भारत सरकार की अनुदान सहायता से और शेष राशि, प्रारंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) से जुटायी जाएगी।" □